

सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य

बनाम

उनके कर्मचारी

मार्च 8,1972

[सी.ए. वैदिलिंगम, आई. डी. दुआ व जी.के. मित्तर, जेजे.]

सीमेंट नियंत्रण आदेश,1961- विनिर्दिष्ट रूप से अधिक मात्रा में उत्पादित सीमेंट के संबंध में अधिक कीमत का भुगतान किया गया-क्या श्रमिक ऐसा अतिरिक्त भुगतान में हिस्सेदार हैं।

सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1961 के तहत भारत सरकार ने अन्तर्गत धारा 18 (जी) उद्योग विकास व विनियम अधिनियम 1951 की शक्तियों के प्रयोग में सीमेंट उत्पादन आदेश में निर्धारित कीमत पर समस्त सीमेंट उत्पाद राज्य व्यापार निगमों को बेचने के लिये बाध्य है। तत्पश्चात उत्पादकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिये उस आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि उत्पादन का उत्पाद निश्चित मात्रा से अधिक है तो उस अधिक मात्रा के लिये उच्च दर पर भुगतान किया जायेगा। अपीलार्थी कंपनियों के कर्मचारियों ने उस भुगतान में अपना हिस्सा की मांग इस तर्क के आधार पर की कि उस अधिक उत्पादन में उनका योगदान है। आयोगिक न्यायाधीकरण ने अपेन पंचाट में निर्धारित किया कि कंपनी व

उसके कर्मचारी इस राशि के 50-50 प्रतिशत के भागीदार हैं। विशेष अनुमति अपील।

अभिनिर्धारित किया:

विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक क्रेता और विक्रेता को इस बात पर सहमत होने से रोकता हो कि विक्रेता निश्चित राशि तक जो भी देने का प्रयास करें वह एक अन्य निश्चित दर से भुगतान होगा और उचित मात्रा का भुगतान उच्च दर से किया जायेगा। संपूर्ण राशि जो विक्रेता प्राप्त करता है वह कीमत कही जाती है। भले ही विक्रय अनुबंध यह दर्शित करता हो कि अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन / बोनस भुगतान के तौर पर मानी जायेगी। कर्मचारियों का यह तर्क कि वे अतिरिक्त भुगतान/ बोनस में हिस्सेदार हैं, किसी भी रूप में मान्य नहीं है। औद्योगिक कानून के तहत जो कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, कर्मचारी ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। [685 एफ, 686 डी]

न्यू मानिक चौक स्पिनिंग एवं विविंग कम्पनी लिमिटेड बनाम टैक्सटाईल लैबर एसोसियेशन [1961] 1 एस.सी.आर.1,मील ऑनर एसोसियेशन बोम्बे बनाम राष्ट्रीय मील मजदूर संघ, बोम्बे [1960], 1 एस.सी.आर.107 श्रीमती तीताघुर पेपर मील्स कम्पनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन,[1959], सप्लीमेंट्री. 2 एस.सी.आर. 1012, बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड

बनाम एम्पलोयेज [1960], 3 एस.सी.आर. 423 व नेशनल एवं स्टील कम्पनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन, [1963] 3 एस.सी.आर. 660, रैफर्ड।

सीमेंट नियंत्रण आदेश भले ही कुछ प्रलोभन अपने उत्पादको को उत्पादन बढ़ाने के लिए देता हो, परंतु फिर भी वह औद्योगिक न्यायाधीकरण को अधिकृत नहीं करता कि वह उसे बोनस के तौर पर कर्मचारियों में विभाजित करे। यह पूर्ण रूप से उत्पादन पर निर्भर करता है कि वह कर्मचारियों को सूचित करे कि नियंत्रण आदेश के तहत उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर अतिरिक्त राशी कंपनी में आएगी एवं उत्पादक उसे प्रोत्साहन/ बोनस के रूप में कर्मचारियों के साथ विभाजित करे, परंतु केवल मात्र इसलिए की उत्पादक सीमा से अधिक उत्पादन किया गया था, इस आधार पर कर्मचारियों को इस बात के लिए अधिकृत नहीं करता कि अतिरिक्त राशी के लिए वे दावा करें एवं औद्योगिक न्यायाधीकरण यह विचार रखने के लिए अधिकारी नहीं था कि क्योंकि उत्पादन में वृद्धि केवल श्रमिकों के सहयोग से हो सकती है, वे स्वतः ही इसके हिस्से के हकदार हो जाते हैं। एक औद्योगिक न्यायाधीकरण केवल वही पंचाट जारी कर सकता है जो विधि अनुमति देता हो। कानून के अभाव में तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत कर्मचारियों का दावा खारिज किया जाता है। [689 डी-एच]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 635/1967.

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण बोम्बे के रैफरेंस (एन टी)-1/1965 के निर्णय दिनांक 11, जनवरी 1967 के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एस.डी. वीमदलाल, के.डी. मेहता, डी.एन. मिश्रा एवं ओ.सी. माथुर प्रत्यर्थी की ओर से।

के. एल. हाथी, प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से।

एम.के. रामामूर्ती और विनित कुमार प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 की ओर से।

निर्णय प्रसारित किया गया।

मित्तर, जे- यह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के एक पंचाट के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है:

"क्या सरकार द्वारा सीमेंट उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भुगतान में हिस्सेदारी की श्रमिकों की मांग उचित है? यदि हां, तो वर्ष 1963 और उसके बाद के वर्षों के लिए भुगतान का आधार और मात्रा क्या होनी चाहिए?"

इसमें उक्त आदेश की अनुसूची में शामिल सिमेन्ट उत्पादकों की संख्या में निर्धारित 14 थी। कुल मिलाकर, ट्रिब्यूनल को पांच सीमेंट उत्पादकों के मामलों में जाने के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्हें कोई प्रोत्साहन भुगतान नहीं मिला था और इन पांच कंपनियों के संबंध में मांग खारिज कर दी गई थी। बचे हुए नौ में से भी तीन निर्माताओं ने अपने

श्रमिकों के साथ समझौता कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप केवल छह के मामले ही विचार के लिए बचे हैं। इस अपील में शामिल कंपनियों के नाम और प्रोत्साहन भुगतान इस प्रकार हैं:-

कंपनी का नाम	1963 के लिए भुगतान।	1964 के लिएभुगतान
1. इंडिया सीमेंट लिमिटेड	56,713-50	22,265-00
2. सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी	शून्य	22,000-00
3. डालमिया डैट्री सीमेंट लिमिटेड	1,19,760-00	1,22,496-00
4. जयपुर उद्योग लिमिटेड	5,16,661-00	शून्य
5. कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वर्क्स लिमिटेड	17,923-00	20,305-00
6. मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	20,86,759-00	शून्य

विवाद की पृष्ठभूमि इस प्रकार है.

"सीमेंट और जिप्सम उत्पाद" उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 3(1) के तहत एक अनुसूचित उद्योग बन गया, जो एक अधिनियम है; कुछ उद्योगों के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान करें। अधिनियम की धारा 2 के तहत भारत संघ को उक्त उद्योग

का नियंत्रण लेने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम के अध्याय III-बी के एस. 18 (जी) (1) शीर्षक "कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, मूल्य आदि का नियंत्रण" के साथ केंद्र सरकार को किसी भी वस्तु की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए सक्षम बनाता है या अधिसूचित आदेश द्वारा किसी भी अनुसूचित उद्योग और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वस्तुओं का वर्ग। उप-एस. एस. 18 (जी) का (2) उप-एस द्वारा समझी गई शक्तियों को दर्शाता है। (1). इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन कीमतों को नियंत्रित करने की शक्तियाँ शामिल हैं जिन पर ऐसी कोई वस्तु या उसका वर्ग खरीदा या बेचा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं के वितरण का विनियमन आदि। 31 अक्टूबर, 1961 को भारत सरकार ने धारा 18 के तहत एक आदेश दिया (छ) 1961 के सीमेंट नियंत्रण आदेश के रूप में जाना जाता है जो 1958 के पहले के आदेश का स्थान लेता है। आदेशों के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

"सीएल. 3. उत्पादकों को निगम को सीमेंट बेचना होगा -(1) प्रत्येक उत्पादक बेचेगा

(1) इस आदेश के प्रारंभ होने की तिथि पर उसके पास स्टॉक में रखी गई सीमेंट की पूरी मात्रा और

(बी) सीमेंट की पूरी मात्रा जो इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख 31 मार्च, 1966 (समावेशी) से पहले उसके द्वारा उत्पादित की जा सकती है,

उस मात्रा को छोड़कर जो उसके और केंद्र के बीच समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। सरकार निगम को, और इसे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वितरित करेगी जो समय-समय पर निगम द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) किसी भी विपरीत अनुबंध के बावजूद, कोई भी निर्माता उप-खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक में रखे गए या उसके द्वारा उत्पादि सीमेंट का निपटान नहीं करेगा।

सी.एल. 6. सीमेंट की नियंत्रित कीमत

(1) वह कीमत जिस पर कोई उत्पादक सीमेंट को इसके अलावा अन्य कीमत पर बेच सकता है

(i) वॉटर-प्रूफ (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट,

(ii) तेजी से सख्त होने वाला सीमेंट और

(iii) कम ताप वाला सीमेंट

अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगा;

(2) (ए) वह कीमत जिस पर निगम सीमेंट बेच सकता है -

(i) वॉटर-प्रूफ (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट;

(ii) तेजी से सख्त होने वाला सीमेंट; और

(iii) कम ताप वाला सीमेंट ;

किसी भी व्यक्ति को रु. रेल गंतव्य रेलवे स्टेशन पर 94.00 प्रति मीट्रिक टन मुफ्त और उस पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क:

बशर्ते कि निगम, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के लिए सरकार को बेची गई स्लैब सीमेंट की कीमत में छूट, छूट या कमीशन की अनुमति दे सकता है:

आदेश की केवल एक अनुसूची थी जो चलती थी;

### अनुसूची

[खंड 6(1) देखें]

वह कीमत जिस पर प्रत्येक उत्पादक रेल पूर्व-कार्यों पर मुफ्त में सीमेंट बेच सकता है, वह कीमत है जो सीमेंट की कीमतों में संशोधन पर टैरिफ आयोग की सिफारिशों के संबंध में उस उत्पादक के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, और कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ। -

(केवल प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है)।

उत्पादक का नाम	कीमत प्रति मीट्रिक टन रुपये।
4. मैसर्स. केसीपी लिमिटेड, माचेरला	69-50
5. मैसर्स. मैसूर आयरन एव स्टील वर्क्स भद्रावती	69-50
8. यूपी सरकार सीमेंट वर्क्स चुरकू (यूपी)	69-50



9. मैसर्स.डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी लिमिटेड	69-50
डालमिया दादरी	
12. मैसर्स. जयपुर उद्योग लिमिटेड,सवाई माधोपुर	69-50
13. मैसर्स. इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड तलैयुथु	72-50
16. मैसर्स. कल्याणपुर नींबू एवं सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, बंजारी	72-50
17. मैसर्स. सोनवैली पोर्ट- भूमि सीमेंट कंपनी लिमिटेड,जपला	72-50
21. मैसर्स. त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड,कोट्टायम	95-00

1963 के संशोधन द्वारा अनुसूची से पहले पैराग्राफ को "पैराग्राफ (बी) और (सी) के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से पहले (ए) के रूप में चिह्नित किया गया था। अनुसूची अनुच्छेद (बी) को पढ़ने के लिए जोड़े जाने के बाद:-

(बी) पैराग्राफ (ए) में निर्दिष्ट मूल्य के अलावा, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित निर्माता उनके द्वारा उत्पादित और बेचे गए सी सीमेंट के संबंध में उक्त तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि ले सकते हैं। उसके कॉलम 3 में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मात्रा।

	निर्माता का नाम.	प्रतिटन अतिरिक्त राशि.	मात्रा की
1	यूपी सरकार सीमेंट	5-50 2,20,000	31 अक्टूबर को

	वर्क्स, चूर्क (उत्तर प्रदेश)		समाप्त होने वाले किसी भी वर्ष में
2.	मैसर्स. केसीपी लिमिटेडमाचेरला	5-50 1,15,000	31 अक्टूबर को समाप्त होने वाले किसी भी वर्ष में
7.	मैसर्स. मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती	5-50 81,000	
9.	मैसर्स. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, डालमिया दादरी	5-50 1,76000	
12.			

गौरतलब है कि अनुसूची में उल्लिखित 21 कंपनियों के संबंध में तीन अलग-अलग कीमतें तय की गई थीं। बारह के लिए लागू कीमत 69-50 रुपये, आठ अन्य के लिए 72-50 रुपये और अकेले एक के लिए 95/- रुपये थी। 1963 में जोड़े गए पैराग्राफ (बी) में निर्माता द्वारा बारह कंपनियों के संबंध में 5-50 रुपये और पांच अन्य के संबंध में 2-50 रुपये की अतिरिक्त राशि के शुल्क का प्रावधान किया गया था। इस तालिका की

दिलचस्प विशेषता यह है कि कॉलम 3 में मात्रा की सीमा निर्माता से निर्माता तक भिन्न होती है और निर्दिष्ट अवधि सभी मामलों में समान नहीं होती है। पहले दो उत्पादकों यूपी सरकार सी सीमेंट व ट वक्स और केसीपी लिमिटेड, माचेरला के लिए, आदेश में 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाले सभी बाद के वर्षों के लिए अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान था। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के मामले में । लिमिटेड, वृद्धि केवल एक वर्ष के लिए प्रदान की गई थी, अर्थात् 31 दिसंबर 1963 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लक्ष्य जिसके ऊपर अतिरिक्त राशि 81,000 मीट्रिक टन का भुगतान किया जाना था। इसी प्रकार, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के मामले में, अतिरिक्त राशि 31 दिसंबर 1963 को समाप्त होने वाले वर्ष में केवल 1,76,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य आंकड़े से अधिक देय थी: जयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में भी लक्ष्य 7 है, 55,000 टन; इंडिया सीमेंट्स के मामले में यह 31 दिसंबर 1963 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए था, साथ ही कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वक्स और सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी के मामले में भी।

ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट नियंत्रण आदेश 1961 में समय-समय पर संशोधन किया गया। 31 मई 1963 के एक आदेश द्वारा जो 1 जून 1963 को लागू होना था और अनुसूची के पैराग्राफ ए के नीचे की अनुसूची में संशोधन किया गया था, ऐसे मामलों में कीमत बढ़ा दी गई थी जहां सीमेंट उत्पादक निगम से 69-50 रुपये प्रति टन से लेकर 72 रुपये तक

शुल्क ले सकते थे। -25 प्रति टन जबकि इंडिया सीमेंट लिमिटेड, कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट लिमिटेड और सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी। लिमिटेड को निगम से 75-25 रुपये वसूलने की अनुमति दी गई। दूसरे शब्दों में, केसीपी लिमिटेड (1970 के सीए संख्या 2156 में अपीलकर्ता) के अलावा उपरोक्त सभी छह उत्पादकों को उक्त निगम को प्रभार्य अपनी कीमत 2-75 रुपये प्रति टन बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। उस कीमत में भी वृद्धि हुई थी जिसे राज्य व्यापार निगम खंड 6 के उप-खंड (2-ए) के तहत वसूल सकता था। 30 जून 1964 और 31 मई, 1965 के संशोधन आदेशों द्वारा कीमतों में और वृद्धि की गई थी। हालांकि ये चिंता का विषय नहीं हैं। इन अपीलों में हमें.

चौदह कंपनियों के कामगारों ने दावा किया कि अनुसूची के पैराग्राफ (बी) के तहत अतिरिक्त राशि केवल उत्पादकों द्वारा उनके अतिरिक्त प्रयास के परिणामस्वरूप अर्जित की जा सकती है और इस तरह वे उसके हिस्से के हकदार थे। विभिन्न उत्पादकों के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग दावे प्रस्तुत किये गये। जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिकों ने दावा किया कि उन्हें वर्ष 1963 के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का 60% और अगले वर्ष में भुगतान की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसके तहत सीमेंट उद्योग को 1963 और उसके बाद के वर्षों में उत्पादित सीमेंट की निर्दिष्ट मात्रा से अधिक पर 5-50 रुपये

प्रति टन की दर से प्रोत्साहन के रूप में भुगतान की अनुमति दी गई थी जयपुर उद्योग लिमिटेड के लिए अपनाया गया आंकड़ा 7,55,000 था और उस आंकड़े से ऊपर उत्पादन से संबंधित 5-50 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त भुगतान था। भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट श्रमिक महासंघ के अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया कि:

"सीमेंट उद्योग में श्रमिकों ने सीमेंट उत्पादन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सहयोग और प्रयासों के बिना प्रत्येक कारखाने में निर्धारित मात्रा को कभी भी पार नहीं किया जा सकता था... प्रत्येक के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा फैक्ट्री पिछले तीन वर्षों में उच्चतम आंकड़े तक पहुंच गई थी और श्रम ने उक्त आंकड़े को पार करने और विभिन्न सीमेंट कार्यों के संबंध में उत्पादन की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और सभी श्रमिकों को प्रोत्साहन भुगतान में पूर्ण भुगतान का हकदार होना चाहिए। सरकार विभिन्न सीमेंट उत्पादकों को वर्ष 1963 और उसके बाद के वर्षों की कमाई के अनुपात में देगी।"

दावे के कुछ बयानों में प्राप्त अतिरिक्त राशि को अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बोनस के रूप में वर्णित किया गया था।

दूसरी ओर, उत्पादकों ने अपने लिखित बयान में कहा कि अतिरिक्त या प्रोत्साहन भुगतान उनकी बिक्री आय का हिस्सा था और वार्षिक लाभ बोनस के भुगतान के उद्देश्य से लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया था। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने कहा कि उनके श्रमिकों को उत्पादन के लक्ष्य के लिए निर्धारित प्रोत्साहन के कुछ पैमानों के अनुसार मूल वेतन के 12 से 40 तक उत्पादन प्रोत्साहन बोनस का भुगतान किया गया था। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि सीमेंट का उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है और दोहराव वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे व्यक्तिगत प्रयास से संबंधित या जोड़ा नहीं जा सकता है या किसी व्यक्तिगत प्रयास से बढ़ाया नहीं जा सकता है और किसी व्यक्तिगत सी सीमेंट का ट कारखाने में किसी भी बढ़े हुए उत्पादन का कारण श्रमिकों की ओर से प्रयास बढ़ाने के बजाय कारखाने का कुशल पर्यवेक्षण और अच्छा प्रबंधन। यह भी कहा गया था कि पूंजी गहन उद्योग होने के कारण उत्पादन में वृद्धि पूंजी निवेश में वृद्धि और बेहतर तकनीकों के कारण हुई थी और अंतिम उत्पाद एक जुड़ी हुई प्रक्रिया का अनुक्रम था जिसमें कोई भी कमी तैयार उत्पाद की मात्रा को कम या धीमा कर सकती थी। इस कंपनी के अनुसार प्रोत्साहन योजना का एकमात्र उद्देश्य, जैसा कि यह लोकप्रिय था, देश में सीमेंट की बढ़ती मांग को यथासंभव पूरा करने के लिए सीमेंट उत्पादकों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कंपनी ने अपनी मशीनरी के पुनर्वास के लिए किए

गए विभिन्न पूंजीगत व्यय का भी उल्लेख किया। सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी के लिखित बयान के अनुसार उसने खदान और कारखाने के लिए नए उपकरणों और भट्ठों और बाइकेबल रोपवे के पुनर्वास के लिए 17,50,000/- रुपये से अधिक का खर्च किया था।

इस अपील में शामिल छह उत्पादकों में से चार द्वारा कुछ विशेष विशेषताओं पर निर्भरता रखी गई थी। जहां तक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का संबंध है, वर्ष 1964-65 के लिए बोनस के भुगतान के संबंध में एक समझौते पर निर्भरता रखी गई थी जिसमें वर्ष 1-4-1964 से 31-3-1965 के लिए भुगतान की जाने वाली राशि पर सहमति व्यक्त की गई थी। उपरोक्त वर्ष के लिए कुल मूल वेतन के 7/24 वें हिस्से की सीमा को कैलेंडर वर्ष 1964 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित प्रोत्साहन बोनस के विचार को शामिल करते हुए लिया जाना था। जयपुर उद्योग के संबंध में, फरवरी के एक समझौते का संदर्भ दिया गया था 4, 1962 जो वर्ष 1960-61 के लिए 10 महीने के वेतन के बराबर बोनस की मांग से उत्पन्न हुआ था। हालाँकि यह एक दीर्घकालिक समझौता था जैसा कि दर्ज की गई शर्तों से स्पष्ट है जिसका प्रभाव श्रमिकों पर था

"वर्ष 1959-60 से 1963-64 तक का बोनस निर्धारित तालिका के अनुसार दिया जायेगा।"

शर्तों के खंड 9 के अनुसार:

"यह सहमति है और स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि संघ के कर्मचारी इस समझौते के तहत कवर किए गए वर्षों के संबंध में सहमत बोनस को छोड़कर किसी भी रूप में और किसी भी नाम से किसी भी बोनस का दावा नहीं करेंगे या इसके हकदार नहीं होंगे।"

शर्तों के खंड 13 से पता चलता है कि यूनियन ने प्रबंधन को आश्वासन दिया कि उत्पादन को उसकी पूर्ण स्थापित क्षमता तक बढ़ाने और बनाए रखने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।

डालमिया दादरी सीमेंट ने अपने कर्मचारियों के साथ वर्ष 1958 से 1963 तक 14 महीने के मूल वेतन के बराबर बोनस देने का समझौता किया। इसमें लाभ और उत्पादन बोनस दोनों शामिल थे। श्रमिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन के साथ सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की कि संयंत्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो।

जहां तक मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का संबंध है। लिमिटेड, प्रबंधन ने कहा कि लिखित बयान के साथ संलग्न परिशिष्ट के अनुसार उत्पादन के लक्ष्य के लिए निर्धारित प्रोत्साहन के पैमाने के अनुसार मूल वेतन के 12 से 40 तक प्रोत्साहन बोनस की योजना पहले से ही अस्तित्व में थी। ऐसा कहा गया था कि यह वार्षिक लाभ बोनस के अतिरिक्त था जो कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 1962-63 और 1963-64 के दौरान महंगाई



भते और अन्य भतों को छोड़कर उनकी कमाई के 1/6 वें की दर से भुगतान किया जा रहा था।

ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों पक्षों में से केवल एक गवाह की जांच की गई। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव आर नटराजन ने उन परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य दिया जिनके तहत सरकार ने सीमेंट उत्पादकों को प्रोत्साहन बोनस देने का निर्णय लिया। उनके अनुसार वर्ष 1962 और 1963 के दौरान सरकार के देश में सीमेंट की आपूर्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए और सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए उत्सुक थी और सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विचार कर रही थी। प्रमुख उत्पादकों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया। विभिन्न विभागों के कामकाज का उचित समन्वय सुनिश्चित करने और मुख्य रूप से कोयले और रेल परिवहन की कठिनाइयों के कारण होने वाली उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए कई सीमेंट कारखानों को संतुलन उपकरण आयात करने की अनुमति दी गई थी। सरकार की कई एजेंसियों की ठोस कार्रवाई से इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए। हालांकि अभी भी प्रयास का एक बड़ा क्षेत्र बाकी था जिसमें निर्माता को अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अपने दिमाग और संसाधनों का उपयोग करना था और अपनी प्रतिभा को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करने की अपनी सरलता का उपयोग करके सीमेंट उद्योग में एक माहौल

बनाना था। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने मेंविशिष्ट कठिनाइयाँ। इसलिए सरकार ने सीमेंट उत्पादकों को प्रत्येक कारखाने में उत्पादित सी सीमेंट की ट की मात्रा के संबंध में 1962 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन के उच्चतम स्तर से अधिक अतिरिक्त कीमत देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। रु. 75/- और यूनिट पर लागू तत्कालीन फैक्ट्री-पूर्व कीमत प्रति टन। इस अतिरिक्त कीमत का भुगतान 1963 और 1964 के दौरान ऐसे उत्पादन पर किया गया था। अपनी जिरह में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का निर्णय जनवरी 1963 में लिया गया था और अधिसूचित किया गया था, लेकिन सरकार और उत्पादकों की संयुक्त बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। गवाह के अनुसार सरकार को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि श्रमिकों को इस अतिरिक्त भुगतान में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं।

कामगारों की ओर से जिस गवाह से पूछताछ की वह सहायक श्रम आयुक्त था जिसे वास्तव में कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया था।

ट्रिब्यूनल के समक्ष उत्पादकों की ओर से यह दिखाने के लिए विभिन्न दलीलें पेश की गईं कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन का श्रमिकों द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रयास से कोई लेना-देना नहीं है। एक दलील यह थी कि कुछ इकाइयों ने उत्पादन बढ़ाने

के उद्देश्य से काफी व्यय किया था। लेकिन जैसा कि ट्रिब्यूनल ने ठीक ही कहा है:

"कंपनी की ओर से कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत नहीं दिया गया, जिससे पता चले कि खर्च ने उत्पादन बढ़ाने में कैसे और किस अनुपात में योगदान दिया है।"

ट्रिब्यूनल ने माना कि उपकरणों पर पूंजीगत व्यय निश्चित रूप से बढ़े हुए उत्पादन में योगदान देगा, लेकिन सबूतों के अभाव में यह इस तरह के योगदान की सीमा निर्धारित करने की स्थिति में नहीं था। ट्रिब्यूनल ने छह में से चार कंपनियों द्वारा भरोसा किए गए विशेष परिस्थितियों की जांच की, लेकिन इसके बावजूद यह विचार किया कि सरकार द्वारा अनुमत प्रोत्साहन भुगतान में हिस्सेदारी की श्रमिकों की मांग उचित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल काफी हद तक किमोर सीमेंट

"चूंकि सरकार ने अपनी अधिसूचना में उद्योग को अधिक उत्पादन के लिए प्रलोभन दिया है, इसलिए हमारी राय में श्रमिकों के दावे पर उसी आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जिस आधार पर "प्रोत्साहन बोनस" के दावे पर विचार किया जाना चाहिए। हम इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। तथ्य यह है कि हमारे सामने जो दावे हैं, वे हर तरह से

प्रोत्साहन बोनस के दावों के बराबर नहीं हैं, उत्पादन के मानक और मानक से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की दर पहले से तय होती है, लेकिन हमने माना है कि दावे इससे पहले कि हम किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में "प्रोत्साहन बोनस" के समान हों। चूंकि यह अतिरिक्त बोनस है जो प्रोत्साहन बोनस की प्रकृति का हिस्सा है, इसकी मात्रा का लाभ से कोई संबंध नहीं हो सकता है और इसे मजदूरी से संबंधित होना चाहिए और इसकी राशि से मापा जाना चाहिए काम।"

वर्क्स के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी वाले एक पुरस्कार से प्रभावित है।

हमारे विचार में उपरोक्त तर्क से प्रभावित होकर ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक दो वर्षों के लिए भुगतान का आधार फिफ्टी फिफ्टी आधार पर होना चाहिए।

हमारे सामने दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए, नियोक्ताओं की ओर से वकील ने तर्क दिया कि जहां तक छह उत्पादकों में से कम से कम चार का संबंध है, विशेष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कामगार इससे अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं। श्रम अपीलीय

न्यायाधिकरण फॉर्मूला या बोनस अधिनियम के तहत स्वीकार्य सामान्य बोनस।

इसके विपरीत, श्रमिकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि श्रमिकों ने 1962 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े को अधिकतम से ऊपर उठाने में कुछ भूमिका निभाई थी और यदि उत्पादकों को कुछ दिया गया था प्रोत्साहन के रूप में ऐसा कोई कारण नहीं था कि श्रमिकों को उसके हिस्से से वंचित किया जाए। श्री राममूर्ति स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि यह स्थापित हो गया है कि किसी विशेष निर्माता के मामले में पर्याप्त पूंजीगत व्यय किया गया है, तो अर्जित अतिरिक्त भुगतान में से आवंटन करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए; लेकिन इससे भी श्रमिकों के कुछ भुगतान के दावे को पूरी तरह नकारना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि निर्माता बाजार में मौजूद स्थितियों के कारण कीमत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र था, तो श्रमिक इस आधार पर बढ़ी हुई कीमत में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकते थे कि यह उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयासों पर आधारित था। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त राशि वसूलने का कारण बाजार में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और इसे सरकार द्वारा वसूलने की अनुमति दी गई थी ताकि उत्पादक अपने श्रम के साथ मिलकर समुदाय के लाभ के लिए उत्पादन का स्तर बढ़ा सकें। पूरा। श्री राममूर्ति द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मामले में

अपील में ट्रिब्यूनल और इस न्यायालय द्वारा परिस्थितियों पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है और अपनाया जाने वाला दृष्टि कोण वह होना चाहिए जो सामाजिक न्याय के अनुरूप हो।

इसके विपरीत उत्पादकों के वकील ने कहा कि सामाजिक न्याय एक अस्पष्ट अवधारणा थी और कानून की अदालतों द्वारा किसी विशेष पाठ्यक्रम को अपनाने को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों को छोड़कर, औद्योगिक कानून का प्रशासन करने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सर्वविदित है कि हमारे देश के अधिकांश उद्योगों में जीवित मजदूरी का उद्देश्य आने वाले लंबे समय तक एक दूर का सपना बना रहेगा और सामाजिक न्याय के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है कि जीवित मजदूरी के बीच असमानता को कम करने के प्रयास किए जाएं। और वास्तविक वेतन, लेकिन औद्योगिक न्यायाधिकरणों को जब भी मौका मिले, अपना रास्ता बनाकर औद्योगिक कानून के स्थापित सिद्धांतों से हटने के लिए स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए।

हालांकि, हमारे विचार में, इस मामले में सामाजिक न्याय के पहलू या यहां तक कि उपरोक्त छह निर्माताओं के कामकाज के संबंध में विशेष विशेषताओं की जांच करना आवश्यक नहीं है। हमें सबसे पहले उस अतिरिक्त भुगतान की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जो उत्पादकों को राज्य व्यापार निगम से प्राप्त हुआ था यानी क्या यह भुगतान योग्य कीमत

के माध्यम से या उसके लिए था, या क्या यह कीमत के सवाल से असंबद्ध था उदाहरण के लिए एक भुगतान के माध्यम से बखशीश श्री राममूर्ति ने प्रस्तुत किया कि यह पहले जैसा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में कोई यह उम्मीद करेगा कि अतिरिक्त भुगतान पूरी उत्पादित मात्रा के साथ जुड़ा होगा और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं होगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैराग्राफ (बी) और 1963 के सीमेंट नियंत्रण आदेश की अनुसूची का अंतर्निहित उद्देश्य यह था कि निर्माता को सरकार की मदद से बाधाओं को कम करने या निर्माता की मदद से उत्पादन बढ़ाने के तरीकों और साधनों को अपनाना चाहिए। स्वयं संबंधित क्लब कामगारों की मदद से उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकरणों का पता लगाना और उन्हें अपनाना, भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को केवल देश में वस्तु की कमी के कारण दी जाने वाली कीमत के रूप में माना जा सकता है। सीमेंट नियंत्रण आदेश, जो कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्पादक अपनी कीमत वसूलने के हकदार नहीं थे। यदि वे होते, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कमी का फायदा उठाते हुए उन्होंने शुरुआत में प्रति टन 69-50 रुपये से कहीं अधिक शुल्क लिया होता। प्रत्येक इकाई अपना जो भी उत्पादन करती है, उसे केवल राज्य व्यापार निगम को और निर्धारित कीमत पर ही बेच सकती है। आदेश के परिणामस्वरूप निगम निर्धारित लक्ष्य से अधिक सीमेंट का उत्पादन करने के लिए निर्माता को

प्रलोभन देने के लिए स्वतंत्र नहीं था क्योंकि इसके बदले में वह वास्तविक उपभोक्ताओं या बाजार में डीलरों से किसी भी अतिरिक्त राशि का शुल्क लेने का हकदार नहीं था। नियंत्रण आदेश के तहत निर्धारित कीमत का एक सीमेंट उत्पादक और राज्य व्यापार निगम के बीच लेनदेन को केवल बिक्री के रूप में वर्णित किया जा सकता है और निगम द्वारा निर्माता को जो भी भुगतान किया गया था उसे केवल कीमत के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

श्री राममूर्ति ने माना कि आम तौर पर एक श्रमिक केवल उपक्रम की सामान्य समृद्धि में हिस्सा ले सकता है और अपने वेतन, महंगाई भत्ते आदि में संशोधन की मांग तब कर सकता है जब नियोक्ता का उत्पादन बढ़ जाता है जिससे उसकी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। वह इस बात पर भी सहमत थे कि सामान्य परिस्थितियों में अधिक उत्पादन से अधिक मात्रा में लाभ होगा, जिससे श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण फार्मूले के तहत या बोनस अधिनियम के तहत उत्पादन बोनस के माध्यम से श्रमिकों का लाभ सुनिश्चित होगा। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में तथ्यों को श्रमिकों के प्रोत्साहन बोनस जैसी किसी चीज़ के दावे को उचित ठहराने के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि इसे उस तरह से नहीं माना जाना चाहिए जिस तरह से इस तरह के बोनस का आमतौर पर दावा किया जाता है या दिया जाता है। दूसरे शब्दों में उनका कहना यह था कि अतिरिक्त भुगतान के प्रलोभन के लिए लक्ष्य का आंकड़ा पार नहीं किया जा सकता



था और चूंकि श्रमिकों के प्रयासों को कुछ हद तक उत्पादन में वृद्धि में योगदान देने के लिए माना जाना चाहिए, इसलिए उन्हें इस तरह का हिस्सा मिलना चाहिए भुगतान किसी भी लाभ का प्रश्न नहीं है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खरीदार और विक्रेता को इस बात पर सहमत होने से रोकता है कि विक्रेता एक निश्चित मात्रा तक जो भी पेशकश कर सकता है, उसके लिए एक विशेष दर पर भुगतान किया जाएगा और उस आंकड़े से अधिक की किसी भी मात्रा के लिए उच्च दर पर भुगतान किया जाएगा। विक्रेता को प्राप्त होने वाली कुल राशि को केवल कीमत ही कहा जा सकता है, भले ही बिक्री का अनुबंध इस तरह से लिखा गया हो कि अतिरिक्त राशि को प्रोत्साहन भुगतान के रूप में माना जाना था। क्रेता और विक्रेता के बीच जो राशि बदलती है अर्थात् बेची गई वस्तु के प्रतिफल को केवल कानूनी शब्दावली में कीमत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सामान्य वाणिज्यिक लेनदेन में कुछ मामलों में, विक्रेता खरीदार को एक निश्चित मात्रा में कमीशन की अनुमति देता है, यदि खरीदार एक निश्चित संख्या से अधिक मात्रा की डिलीवरी लेता है। इसका मतलब केवल यह होगा कि खरीदार उस मामले की विशेष परिस्थितियों में कीमत में कमी की अनुमति दे रहा था। सीमेंट नियंत्रण आदेश के तहत क्या हुआ है कि बिक्री की शर्तें आदेश के तहत सरकार द्वारा तय की जाती हैं,

पार्टियों यानी उत्पादकों और निगम को शर्तों पर स्वयं चर्चा करने और तय करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

सरकार ने माना कि जब तक वह उत्पादकों को पैराग्राफ (ए) की अनुसूची के तहत तय कीमत से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति देकर उन्हें प्रेरित नहीं करती, तब तक बाजार में वस्तु की कमी कम होने की बहुत कम संभावना थी। हालांकि, उसी समय यह एहसास हुआ कि उत्पाद के पूरे उत्पादन पर कीमत में सामान्य वृद्धि से राज्य निगम के लिए ठीक से काम करना मुश्किल हो जाएगा जब तक कि वह निगम को उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति न दे। यह केवल इसलिए था क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़े, इसलिए उसने 1962 तक के उत्पादन के आंकड़ों पर केवल इस अतिरिक्त मात्रा के संबंध में अतिरिक्त राशि वसूलने की व्यवस्था अपनाई।

हालांकि इस मामले का एक और पहलू भी है। यह मानते हुए कि अतिरिक्त भुगतान को प्रोत्साहन भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए और वर्णित किया जाना चाहिए, यह देखना मुश्किल है कि औद्योगिक कानून के तहत कर्मचारी इस तरह के भुगतान के किसी भी हिस्से पर दावा कैसे कर सकते हैं, जिसे इस न्यायालय ने अब तक समझाया है। न्यू मानेक चौक एसपीजीमें। और Wvg. सह. लिमिटेड वी. टेक्सटाइल एसो सिएशन, (1961) 3 एससीआर 1 एट पी। 9 इस न्यायालय ने औद्योगिक न्यायाधिकरण और

इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा इस देश के औद्योगिक कानून में शामिल बोनस की अवधारणा की जांच की। यह विचार किया गया कि चार प्रकार के बोनस हैं जो औद्योगिक कानून के तहत विकसित किए गए थे, अर्थात्, (1) उत्पादन बोनस या प्रोत्साहन वेतन, (2) पार्टियों के बीच अनुबंध की एक निहित अवधि के रूप में बोनस, (3) प्रथागत बोनस मिल मालिक एसोसिएशन बॉम्बे बनाम में श्रम अपीलिय न्यायाधिकरण द्वारा विकसित कुछ त्यौहार और (4) लाभ बोनस के संबंध में । राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बॉम्बे, (1950) 2 लैब एलजे 1247 (एफबी) (एलएटीआई-बॉम)। बड़े हुए उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बोनस उत्पादन बोनस की प्रकृति का हिस्सा है। मैसर्स में. टीटाघुर पेपर मिल्स, कंपनी. लिमिटेड वी. इट्स वर्कमेन, (1959), इस न्यायालय को उत्पादन बोनस की प्रकृति की जांच करनी थी। इस न्यायालय के अनुसार (पृष्ठ 1019 पर देखें):

यह उच्च उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन है और एक प्रोत्साहन मजदूरी की प्रकृति में है।"

स्मिथ द्वारा श्रम कानून का जिक्र। दूसरा संस्करण, पृ. 723, जहां अन्य देशों में प्रचलित विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहन वेतन योजनाओं के रूप में जाना जाता है, विभिन्न आधारों पर काम किया गया है, न्यायालय ने कहा:

"ऐसी योजनाओं में सबसे सरल स्ट्रेट पीस-रेट योजना है जहां उत्पादित प्रत्येक पीस के अनुसार भुगतान किया जाता है, कुछ मामलों में इतने घंटों के काम के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी होती है। लेकिन स्ट्रेट पीस-रेट प्रणाली वहां काम नहीं कर सकती जहां समाप्त हो जाती है उत्पाद बड़ी संख्या में श्रमिकों के सहकारी प्रयास का परिणाम है, प्रत्येक के पास एक छोटा सा हिस्सा होता है जो परिणाम में योगदान देता है। ऐसे मामलों में, उत्पादित टन भार द्वारा उत्पादन बोनस दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में है। एक आधार है या मानक जिसके ऊपर अतिरिक्त उत्पादन के लिए मूल वेतन के अतिरिक्त अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। लेकिन योजना की प्रकृति जो भी हो, भुगतान प्रभावी होता है जो कि तय किए गए मानक से अधिक श्रमिकों द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयास के लिए एक अतिरिक्त पारिश्रमिक है। अतिरिक्त भुगतान अतिरिक्त लाभ पर नहीं बल्कि अतिरिक्त उत्पादन पर निर्भर करता है। इसलिए, आम तौर पर उत्पादन बोनस का भुगतान आगे की परिलब्धियों के भुगतान से अधिक या कम नहीं है श्रमिकों को मानक प्रदर्शन से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन पर निर्भर करना

। इस मामले में उत्पादन बोनस भी इसी प्रकृति का है और उच्च उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त पारिश्रमिक से अधिक कुछ नहीं है।"

ऐसी योजना की शुरुआत के संबंध में न्यायालय के समक्ष तर्क यह था

"विशेष रूप से उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला है और यह कई जटिल कारकों पर विचार करने पर निर्भर करता है, अर्थात्, बाजार की स्थिति, उत्पाद की मांग, कीमतों की सीमा, और इसी तरह। इसलिए, यह पूरी तरह से नियोक्ता पर निर्भर है कि वह उत्पादन बोनस योजना शुरू करे या नहीं।"

इस सवाल पर कि क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास उत्पादन बोनस योजना शुरू करने का अधिकार क्षेत्र हो सकता है, न्यायालय ने प्रश्न खुला छोड़ दिया लेकिन यह विचार किया कि जबकि न्यायालय के समक्ष मामले में उत्पादन बोनस की एक योजना अस्तित्व में थी, ट्रिब्यूनल के पास औद्योगिक विवादित अधिनियम के तहत इससे निपटने और इसमें उचित संशोधन करने का अधिकार क्षेत्र था। इसी तरह का विचार बर्न एंड कंपनी में व्यक्त किया गया था । लिमिटेड, वी . उनके कर्मचारी, (1960)

3 एससीआर 423 और नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम । देयर वर्कमेन , (1963) 3 एससीआर 660

विधानमंडल किसी भी प्रकार के बोनस को शुरू करने के लिए निश्चित रूप से हमेशा खुला रहेगा, जिसे अब तक ट्रिब्यूनल या इस न्यायालय द्वारा विकसित औद्योगिक कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन यह एक ठोस आधार पर टिका होना चाहिए और उस प्रभाव के लिए व्यक्त शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि इस विषय पर कोई अंतिम दृष्टिकोण व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, हम यह सोचते हैं कि कानून के अलावा उत्पादन में वृद्धि के लिए एक प्रोत्साहन बोनस, इस सवाल के बावजूद कि उद्योग लाभ कमा रहा था या नहीं, एक ऐसी चीज़ है जिसे पेश किया जाना चाहिए। उद्योग की विशेष इकाई द्वारा. यह तय करना प्रबंधन का काम होगा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों को क्या प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का यह मानना उचित नहीं होगा कि केवल इसलिए कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, श्रमिक ऐसी वृद्धि के कारण बोनस का दावा करने का हकदार होगा। श्रमिक निस्संदेह वेतनमान, महंगाई भत्ता और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों में संशोधन के साथ-साथ लाभ बोनस का भी हकदार होगा; लेकिन कानून या प्रोत्साहन उत्पादन की योजना के अभाव में, औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा स्वयं एक योजना बनाना उचित नहीं होगा।

हमारे विचार में सीमेंट नियंत्रण आदेश भले ही उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन की पेशकश करता हो, लेकिन उसकी शर्तों ने ट्रिब्यूनल को इसे प्रोत्साहन बोनस के रूप में मानने का अधिकार नहीं दिया, जिसमें कामगार हिस्सा ले सकते थे। यह निश्चित रूप से निर्माता पर निर्भर था कि वह श्रमिकों को सूचित करे कि नियंत्रण आदेश की शर्तों के तहत यदि उत्पादन बढ़ाया गया तो कंपनी को अतिरिक्त धनराशि मिलेगी और निर्माता तय कर सकता था कि श्रमिकों को क्या प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन केवल इसलिए कि पैसे की एक अतिरिक्त राशि, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कीमत के रूप में और कंपनी के खाते में चली जाएगी क्योंकि उत्पादन लक्ष्य पार हो गया था; कामगार व वास्तव में अतिरिक्त राशि के लिए दावा करने के हकदार नहीं हैं और औद्योगिक न्यायाधिकरण यह विचार करने का हकदार नहीं है कि चूंकि उत्पादन में वृद्धि केवल कामगारों के सहयोग से ही हो सकती है, इसलिए वे स्वचालित रूप से इसके हकदार बन जाते हैं। उसका एक हिस्सा ऐसा हो सकता है कि उन सभी को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण फॉर्मूले के तहत लाभ बोनस के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान का लाभ मिला हो और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोत्साहन बोनस के दावे पहले उल्लिखित कई कंपनियों में कमजोर आधार पर आधारित थे। यह शायद ही ऐसा मामला होगा जहां हमें इतने दूरगामी महत्व का एक सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए, जैसे कि कामगार प्रोत्साहन बोनस

के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान के हकदार हैं, जैसे ही वे यह स्थापित कर सकें कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादन उच्चतम से अधिक हो गया है। पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा. न ही हम किमोर के मामले में पुरस्कार की शर्तों को इस रूप में देख सकते हैं कि औद्योगिक न्यायनिर्णयन को क्या दिशा लेनी चाहिए। एक औद्योगिक अदालत केवल वही फैसला दे सकती है जिसकी कानून अनुमति देता है। इस विषय पर कानून के अभाव में और मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन भुगतान योजना के अभाव में, हम श्रमिकों के इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दें देंगे ।

इसके परिणामस्वरूप हम अपील की अनुमति देते हैं लेकिन लागत के अनुसार आदेश देंगे।

जी.सी

अपील की अनुमति



यह अनुवाद आर्टिफिशियल टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीतू भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।